



Ch
11/7/86

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 344] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 9, 1986/अषाढ़ 18, 1908
No. 344] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 9, 1986/ASADHA 18, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 1986

अधिसूचना

सं. 362/86—केन्द्रीय उत्पादशुल्क

मा. का. नि. 941(अ) :—केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उस प्रथा के अनुसार जो केन्द्रीय उत्पादशुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 के अधीन उत्पादशुल्क के उद्ग्रहण (जिसके अन्तर्गत उसका अनुद्ग्रहण भी है), की बाबत साधारणतः विद्यमान थी, उक्त अधिनियम की, ओ अधिनियम केन्द्रीय उत्पादशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) के प्रारंभ के पूर्व विद्यमान था, पहली अनुसूची के मद सं. 38 के अन्तर्गत आने वाली माविसों पर जिनकी निर्यात अन्य विनिर्माता के लेबल के अधीन (ऐसा विनिर्माता जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 22/82-

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 23 फरवरी, 1982 की अधिसूचना में अन्तर्षिष्ट छूट के लिए (अस्थायी पात्र है) की गई है, उत्पादशुल्क 17 मार्च, 1985 से प्रारंभ होने वाली और 11 सितम्बर, 1985 को समाप्त होने वाली कालावधि के दौरान प्रत्येक 50 माचिसों के 1 60 अपए प्रति ग्रुस बक्सों से अधिक उद्ग्रहीत नहीं किया जा रहा था ;

अब अतः केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पादशुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 11ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निवेश देती है कि ऐसी माचिसों पर उक्त अधिनियम के अधीन संदेय उत्पादशुल्क का वह समस्त भाग जो उक्त प्रथा के कारण देय नहीं है, ऐसी माचिसों की बाबत जिन पर उक्त उत्पादशुल्क उक्त प्रथा के अनुसार उक्त अवधि के दौरान कम उद्ग्रहीत किया गया था, संदेय किए जाने की अपेक्षा नहीं होगी।

[फा. सं. ब. 37/15/85-टी.आर.यू.]

के एस. वेंकटगिरि, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 9th July, 1986

NOTIFICATION

No. 362/86-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 941 (E) :—Whereas the Central Government is satisfied that according to a practice that was generally prevalent regarding levy of duty of excise (including non-levy thereof) under section 3 of the Central Excises and salt Act, 1944 (1 of 1944), duty of excise on matches, falling under Item No. 38 of the First Schedule to the said Act, as that Act existed prior to the commencement of the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), cleared under the label of another manufacturer (such manufacturer being otherwise eligible for the exemption contained in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 22/82-Central Excises, dated the 23rd February, 1982), was not being levied in excess of Rs. 1.60 per gross boxes of 50 matches each during the period commencing on the 17th March, 1985 and ending with the 11th September, 1985 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 11C of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby directs that the whole of that portion of duty of excise payable under the said Act on such matches, but for the said practice, shall not be required to be paid in respect of such matches on which the said duty of excise was short-levied during the said period in accordance with the said practice.

[F. No. B. 37/15/85-TRU]

K. S. VENKATAGIRI, Under Secy.